भारत की अस्वस्थ डेटा प्रणाली को नया स्वरूप देना

लेखक- आर.बी. बर्मन (पूर्व अध्यक्ष, राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग)

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-III (भारतीय अर्थव्यवस्था) से संबंधित है।

द हिन्दू

21 जनवरी, 2020

"वर्तमान राष्ट्रीय लेखांकन और विश्लेषणात्मक ढाँचा एक जटिल अर्थव्यवस्था के कई प्रमुख आयामों को नजरअंदाज करता है।"

आधार के रूप में 2011-12 के साथ सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के आँकड़ों की नई श्रृंखला, जिसे 2015 में जारी किया गया, विश्लेषकों को उचित नहीं प्रतीत हुआ और ऐसा इसलिए क्योंकि कुछ समय के लिए रोजगार-बेरोजगारी के आँकड़ों को रोका गया और उपभोक्ता व्यय डेटा को जारी नहीं किया गया। राष्ट्रीय सांख्यिकी सर्वेक्षण कार्यालय (NSSO) को राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के अंतर्गत लाना, शासी परिषद और फिर राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के तहत् लंबे समय से चली आ रही व्यवस्था में फेरबदल करना संदेह पैदा करता है। जैसा कि आधिकारिक आँकड़े लोकहित में है, अर्थव्यवस्था की स्थिति और शासन की सफलता के बारे में जानकारी देने के लिए इसे निष्पक्ष होने के साथ-साथ स्वतंत्र होने की भी आवश्यकता है।

व्यापक प्रभाव

जीडीपी दोहराव के बिना वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए सभी उत्पादक गतिविधियों को कवर करता है। इसके फलस्वरूप यह मूल्य के तंत्र के माध्यम से सेब और संतरे, ट्रैक्टर और हँसिया, व्यापार, परिवहन, भंडारण और संचार, रियल एस्टेट, बैंकिंग और सरकारी सेवाओं को जोड़ता है। नेशनल अकाउंटिंग प्रणाली को अर्थव्यवस्था के प्रदर्शन का आकलन करने के लिए उत्पादन, खपत, आय और धन के संचय को मापने के लिए डिजाइन किया गया है।

जीडीपी डेटा बाजार, निवेश, धन का प्रवाह और भुगतान संतुलन को प्रभावित करता है। इनपुट-आउटपुट संबंध उत्पादकता और संसाधनों के आवंटन मांग और आपूर्ति की कीमतों विनिमय दरों मजदूरी दरों रोजगार जीवन स्तर और जीवन के सभी क्षेत्रों को प्रभावित करती है।

जीडीपी के आँकड़ों पर शुरू में मौजूदा कीमतों का अनुमान लगाया जाता है। समय और क्षेत्रों की तुलना के लिए वास्तविक मात्रा के लिए मूल्य को समायोजित करने के मूल्य प्रभाव को अलग करना आवश्यक है। उचित मूल्य सूचकांक के माध्यम से मूल्य प्रभाव को समायोजित किया जाता है। वर्तमान श्रृंखला को मूल्य समायोजन के लिए गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ा, विशेष रूप से सेवा क्षेत्र के लिए, क्योंकि अधिकांश सेवा क्षेत्रों के लिए उचित मूल्य सूचकांकों की अनुपस्थिति में सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 60% योगदान है। 2014-17 में कम और नकारात्मक क्षेत्र में जाने वाले मूल्य सूचकांक ने वास्तविक विकास को विकृत कर दिया।

कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय MCA21 के साथ वार्षिक सर्वेक्षण (ASI) की जगह, उद्यम दृष्टिकोण के लिए स्थापना से बदलाव ने डेटा और कार्यप्रणाली संबंधी गंभीर मुद्दों को पेश किया। डब21 डेटा का उपयोग करना और उसके बाद बंद हो चुके उद्यमों को हटाए बिना कारकों को हटाना और फिर तुलनीय एएसआई डेटा की मैपिंग पर अपर्याप्त कार्य, एक और अभाव है।

अपरिवर्तित दृष्टिकोण

आँकड़ों को संग्रह करने वाला दृष्टिकोण लंबे समय तक एक समान ही रहता है अर्थात मूल्य और उत्पादन सूचकांकों का निर्माण एक निश्चित आधार लासपेयर इंडेक्स का उपयोग करके किया जाता है, धान के लिए उपज दर फसल कटाई प्रयोगों द्वारा अनुमानित की जाती है और रोजगार-बेरोजगारी, उपभोक्ता व्यय, औद्योगिक उत्पादन, संपत्ति और देनदारियों पर डेटा संग्रह के लिए

क्षेत्र सर्वेक्षण संगठन कायम है। जब उत्पादन की उत्पादकता और पारिश्रमिक मूल्य कृषि के लिए प्रमुख चिंता का विषय है, तो मिट्टी की स्थिति, नमी, तापमान, पानी और उपज का निर्धारण करने के लिए उर्वरक का उपयोग जैसे कारकों पर डेटा एकत्र करना आवश्यक बन जाता है। उदाहरण के लिए, इजराइल उत्पादकता का समर्थन करने के लिए विश्लेषण के लिए इन आँकड़ों को एकत्र करता है। ई-गवर्नेंस के तहत् किये गए पहल ने विशाल आँकड़ों को प्राप्त करने में मदद की, जिसे आधिकारिक आँकड़ों के प्रस्तुतीकरण के लिए उनके सार्थक उपयोग के लिए समेटा जाना चाहिए। आधुनिक की प्रक्रिया के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग कर संग्रह करने की आवश्यकता है।

डेटा लॉजिस्टिक्स

जीडीपी के साथ, हमें प्रतिस्पर्धा, समावेशी विकास, इंटरनेट ऑफ थिंग्स से जुड़ी चौथी पीढ़ी की औद्योगिक क्रांति, जैव प्रौद्योगिकी, रोबोटिक्स- प्रवृत्त रोजगार और उत्पादकता, पर्यावरण संरक्षण, सतत् विकास और सामाजिक कल्याण को आंकने के लिए डेटा की आवश्यकता है। इसलिए जीडीपी डेटा को गहन अंतर्दृष्टि के लिए अन्य डेटा के होस्ट के साथ जोड़ा जाना चाहिए। हमें मौजूदा सिस्टम को फिर से सुदृढ़ करने की जरूरत है, जो कि आवश्यक डेटा के साथ एकीकृत प्रणाली का निर्माण करे। 2024-25 तक 5 ट्रिलियन डॉलर वाली अर्थव्यवस्था के लक्ष्य का पीछा करने के लिए जनसांख्यिकीय लाभांश का उपयोग करते हुए हमें निवेश की माँग के लिए अप्रयुक्त संसाधनों को लक्षित करना चाहिए।

हम अकेले समितियों की स्थापना करके डेटा विसंगतियों को समेट नहीं सकते। हमें उन प्रणालियों की आवश्यकता है जो विश्वसनीयता, वैधता, स्थिरता और सुसंगतता के साथ डेटा की एक विशाल मात्रा को संरक्षित कर सके। जिसके लिए बेहतर प्रौद्योगिकी की आवश्यकता होगी।

साथ ही ऐसी समितियों के पास ऑडिट के लिए एक समर्पित टीम का समर्थन होना चाहिए और लालफीताशाही को हटाकर फैसलों को लागू करने की क्षमता होनी चाहिए। हालाँकि, यह रंगराजन आयोग की विचारशील और अच्छी तरह से महत्वपूर्ण प्रमुख सिफारिशों के रूप में वांछित है। राष्ट्रीय सांख्यिकीय आयोग को 2006 के बाद से सिफारिशों को लागू करने में बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है।

वर्तमान और भविष्य

वर्तमान राष्ट्रीय लेखांकन और विश्लेषणात्मक ढाँचा एक जटिल अर्थव्यवस्था के कई प्रमुख आयामों को नजरअंदाज करता है। हमें ऐसी जटिल प्रणाली और विकासवादी प्रक्रिया के विश्लेषण के लिए एक नए ढाँचे की आवश्यकता है। लाभप्रदता, संरचनात्मक परिवर्तन और सामान्य कल्याण को प्रभावित करने वाली बढ़ती बाजार शक्ति, स्वचालन, रोबोटाइजेशन और अन्य श्रम-प्रतिस्थापन प्रौद्योगिकियों पर कई सवाल उठ रहे हैं।

हमें बेरोजगार और खोए हुए रोजगार के लिए वैकल्पिक रास्ते तलाशने होंगे। दक्षता और स्थिरता को इंजेक्ट करने के लिए हमें विस्तृत डेटा की आवश्यकता है। हमें बाजार के माइक्रोस्ट्रक्चर प्रौद्योगिकी और उन्नत अनुसंधान की भूमिका, मानव कौशल पर बदलती माँग के बारे में अधिक विस्तार से जानने की आवश्यकता है। एकाधिकार शक्ति, अकुशल इनपुट-आउटपुट मिश्रण, डंपिंग, अप्रचलित प्रौद्योगिकी और उत्पादन मिश्रण के माध्यम से अर्थव्यवस्था को होने वाले घातक नुकसान को समाहित किया जाना चाहिए।

आधुनिक नेटवर्क वाली अर्थव्यवस्था के सामाजिक आर्थिक विकास में डेटा का महत्त्व अधिक है। अर्थशास्त्र अब प्रतिस्पर्धात्मकता, जोखिमों, अवसरों और सामाजिक कल्याण को मापने, प्रभावित करने और व्यापक रूप से आगे बढ़ने के साथ डेटा में निहित है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत मानकों, स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप, बहु-विषयक विश्लेषिकी के अनुरूप इन आँकड़ों का निर्माण पारदर्शी तरीके से किया जाना चाहिए। चूँकि ये आँकड़े सरकार के प्रदर्शन को प्रतिबिंबित करते हैं, इसलिए यह आवश्यक है कि इसकी स्वतंत्रता को बनाए रखा जाए।

सीएसओ और एनएसएसओ का विलय

चर्चा में क्यों?

- पिछले वर्ष सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय (एनएसएसओ) और केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय (सीएसओ) का राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) में विलय करने का निर्णय लिया था।
- भारतीय आधिकारिक सांख्यिकी प्रणाली के संबंध में सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के कामकाज को सुव्यवस्थित और मजबूत करने तथा मंत्रालय के भीतर प्रशासनिक कार्यों को एकीकृत करके अधिक तालमेल बैठाने के लिए यह कदम उठाया गया था।

मुख्य बिंदु

- नई व्यवस्था के तहत् सांख्यिकी शाखा मुख्य मंत्रालय का एक अभिन्न हिस्सा होगा।
- इस सांख्यिकी शाखा में एनएसओ के साथ घटक के रूप में सीएसओ और एनएसएसओ शामिल होंगे।
- एनएसएसओ की अध्यक्षता सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन सचिव करेंगे। इसके विभिन्न विभाग महानिदेशक (डीजी) के जरिए सचिव को रिपोर्ट करेंगे।
- केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय (सीएसओ) वृहद आर्थिक आँकड़े जैसे जीडीपी वृद्धि, औद्योगिक उत्पादन और मुद्रास्फीति के आँकड़े जारी करता है। इसका प्रमुख महानिदेशक होता है।

नये विभाग और उनके कार्य

- एनएसएसओ के डेटा प्रसंस्करण विभाग (डीपीडी) का नाम डेटा क्वालिटी एश्योरेंस विभाग (डीक्यूएडी) होगा।
- इस पर सर्वेक्षण के आँकड़ों और गैर सर्वेक्षण आँकड़ों की गुणवत्ता में सुधार लाने की जिम्मेदारी होगी। गैर सर्वेक्षण डेटा में आर्थिक गणना और प्रशासनिक आँकड़ों जैसी चीजें शामिल हैं।
- इसी प्रकार, एनएसएसओ का फील्ड ऑपरेशन विभाग (एफओडी) मंत्रालय का अधीनस्थ कार्यालय होगा।
- सीएसओ, एनएसएसओ के अन्य सभी विभाग और प्रशासनिक शाखा मंत्रालय के अन्य विभागों के रूप में मौजूद रहेंगे।
- आदेश में राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग (एनएससी) को लेकर कुछ भी नहीं कहा गया। यह देश में सांख्यिकी कार्यों की निगरानी करता है। सरकार ने जून 2005 को एनएससी की स्थापना की थी।

CSO के बारे में

- केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन (सीएसओ) भारत में सांख्यिकीय गतिविधियों के समन्वय एवं सांख्यिकीय मानकों के विकास एवं अनुरक्षण हेतु उत्तरदायी संगठन है।
- यह संगठन सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय भारत सरकार के अंतर्गत्त कार्य करता है। इसके कार्यकलापों में राष्ट्रीय लेखा के संकलन, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक का संकलन, उद्योगों का वार्षिक सर्वेक्षण और आर्थिक गणना का आयोजन तथा उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का संकलन भी शामिल है।
- केंद्रीय सांख्यिकीय कार्यालय के प्रमुख महानिदेशक की सहायतार्थ हेतु पांच अपर महानिदेशक होते हैं जो राष्ट्रीय लेखा प्रभाग, सामाजिक सांख्यिकी प्रभाग, अर्थ-सांख्यिकी प्रभाग, प्रशिक्षण प्रभाग और समन्वय एवं प्रकाशन प्रभाग का कार्य देखते हैं।

Comm

संभावित प्रश्न (प्रारंभिक परीक्षा)

प्र. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. MCA-21 भारत सरकार के कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय का ई-शासन पहल है।
2. नेशनल अकाउंटिंग प्रणाली (SNA) के जरिए अर्थव्यवस्था के प्रदर्शन का आकलन किया जाता है।
3. जी.डी.पी. डेटा बाज़ार, निवेश धन का प्रवाह और भुगतान संतुलन को प्रभावित करता है।

उपर्युक्त में से कौन-से कथन सत्य हैं?

(a) 1 और 2 (b) 2 और 3

(c) 1 और 3 (d) 1, 2 और 3

Expected Questions (Prelims Exams)

1. Consider the following statements:

1. MCA-21 is an e-Governance initiative of the Ministry of Corporate Affairs, Government of India.
2. The performance of the economy is measured through the System of National Accounts (SNA).
3. GDP data affects the market, flow of investment and balance of payments.

Which of the above statements are correct?

(a) 1 and 2 (b) 2 and 3

(c) 1 and 3 (d) 1, 2 and 3

नोट : 20 जनवरी को दिए गए प्रारंभिक परीक्षा (संभावित प्रश्न) का उत्तर 1 (d) होगा।

संभावित प्रश्न (मुख्य परीक्षा)

प्रश्न: 'वर्तमान विश्व व्यवस्था में कोई भी देश डेटा के तार्किक उपयोग से ही विकास के पथ पर अग्रसर हो सकता है।' इस कथन के संदर्भ में भारत के डेटा प्रणाली और संबन्धित संस्थागत संरचना की चर्चा कीजिए।

(250 शब्द)

'In the current world order, any country can move on the path of development only with the logical use of data.' In the context of this statement, discuss India's data system and related institutional structure.

(250 words)

नोट :- अभ्यास के लिए दिया गया मुख्य परीक्षा का प्रश्न आगामी UPSC मुख्य परीक्षा को ध्यान में रख कर बनाया गया है। अतः इस प्रश्न का उत्तर लिखने के लिए आप इस आलेख के साथ-साथ इस टॉपिक से संबंधित अन्य स्रोतों का भी सहयोग ले सकते हैं।